Statement-II

Statewise allocation of funds under Ist stream of JRY during 1993-94

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	State	Central Allocation
1.	Andhra Pradesh	4995
2.	Bihar	13735
3.	Gujarat	3110
4.	Jammu & Kashmir	633
5.	Karnataka	3772
6.	Madhya Pradesh	12195
7.	Maharashtra	8174
8.	Orissa	5715
9.	Rajasthan	3655
10.	Tamil Nadu	2504
11.	Uttar Pradesh	6558
12.	West Bengal	4900
	TOTAL :	70256

बिहार के गांवों में पेय जल की उपलब्धता

3237. **श्री एस० एस० अहलुवालिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि बिहार के अधिकांश ग्रामीण भागों में लोग पीने, नहाने, धोने और पकाने के लिए तालाबों के दूषित जल का प्रयोग करते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल की गुणवत्ता के लिए सर्वेक्षण

3238. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेय जल की गुणवत्ता के संबंध में राज्यों को निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा; और

(ग) उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण के भाग–1 के आंकडे अभी तक 23 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हो चुके हैं । पेयजल की गुणवत्ता के बारे में सर्वेक्षण के भाग–2 से संबंधित आंकड़े 6 राज्यों से प्राप्त हुए हैं । आंकडों का विश्लेषण करते समय बड़े पैमाने पर अनियमिततायें पाई गई थीं। सभी राज्य सरकारों से आंकड़ों की पुनः पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सही किए गए आकड़ें अभी प्राप्त होने हैं । यह भी निर्णय लिया गया है कि बिना जल स्रोत वाली मुख्य बस्तियों और 30% अन्य बस्तियों की पूरी जांच भी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा ही कराई जाए ।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित राशि

3239. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा जारी की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दी गई राशि आवश्यकता से कम थी जिसके कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) और (ख) 1991 92 और 1992–93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के सूखा प्रभावित जिलों सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को आवंटित और रिलीज की गई केंद्रीय निधियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं, (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) जी नहीं । देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आवंटित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त 1993–94 के दौरान देश के 120 चयन किए गए पिछडे जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना के अतिरिक्त निधियां आवंटित की गई हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुतायत है । गहन जवाहर रोजगार योजना के लिए चहन किए गए पिछडे जिलों की सूची में उन जिलों को शामिल किया गया है जिनके अधिकांश खण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा कवर होते हैं ।

उत्तर प्रदेश को सुनिश्चित रोजगार योजना जिसे 2 अक्टूबर, 1993 से देश के सभी पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खन्डों में आरंभ किया गया है । जिनमें उत्तर प्रदेश के 145 खंड शामिल हैं, के अंतर्गत भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ये खंड देश के दूर-दराज और पिछडे क्षेत्रों में स्थित हैं और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर होते हैं ।